महत्वपूर्ण

संख्या-14/2016/1957/31-2016-43/2015 टी0सी0

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2016**

विषयः- प्रदेश की 52 महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं पर समीक्षा एवं प्रगति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-01/2016/58/31-2016-43/2015 दिनांक 8 जनवरी, 2016 द्वारा उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा, वर्ष 2016-17 एवं शासनादेश संख्या-08/2016/1149/ 31-2016-43/2015 दिनांक 10 मई, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु विकास प्राथमिकता कार्यक्रम चिन्हित कर जारी किए गए हैं। उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित एजेण्डा बिन्दुओं/प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन एवं समीक्षा पूर्व की भाँति यथावत की जाएगी।

2. इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में 51 विकास प्राथमिकताएं चिन्हित की गई थी। आई0 स्पर्श योजना को भी सम्मिलित करने के उपरान्त अब 52 महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताएं (संलग्न) चिन्हित हैं। इन महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं को विभागीय समय सारिणी के अनुसार क्रियान्वित करने हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इन प्राथमिकताओं का समुचित लाभ जनता तक ससमय पहुँच सके।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन 52 महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं का ससमय क्रियान्वयन किए जाने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

क- जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त द्वारा इन महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की प्रत्येक 10 दिनों के अन्तराल पर समीक्षा की जाएगी यदि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अवगत कराया जाए। प्रमुख सचिव/सचिव समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित कराएगें।

ख- जिलाधिकारी द्वारा पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की माह जून, 2016 तक की प्रगति 10 दिनों के अन्दर एवं माह दिसम्बर, 2016 तक की प्रगति दिनांक 10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनवरी, 2017 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को हार्ड एवं साफ्ट कापी में ईमेल आईडी- **kkvuplko@gmail.com** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

ग- इसी प्रकार प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा भी इन महत्वपूर्ण योजनाओं में से अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं/प्राथमिकताओं की प्रत्येक 10 दिनों के अन्तराल पर समीक्षा की जाएगी।

घ- प्रमुख सचिव/सचिव इन प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हुए जनपद/मण्डल तथा शासन स्तर पर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित कराएंगे तथा पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में शासन स्तर पर की गई अपेक्षित कार्यवाही की माह जून, 2016 तक की प्रगति 10 दिनों के अन्दर एवं माह दिसम्बर, 2016 तक की प्रगति दिनांक 10 जनवरी, 2017 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को हार्ड एवं साफ्ट कापी में ईमेल आईडी- **kkvuplko@gmail.com** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाए।

4- पुनः स्पष्ट करना है कि पूर्व में जारी विकास एजेण्डा के बिन्दुओं/कार्यक्रमों पर पूर्व की भांति प्रगति समीक्षा करते हुए इन महत्वपूर्ण 52 प्राथमिकताओं पर ससमय प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विशेष फोकस प्रदान किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव।

संख्या-14/2016/1957(1)/31-2016-43/2015 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

महत्वपूर्ण प्राथमिकतायें

1.	कानून व्यवस्था	(गृह विभाग)
2.	स्टेट डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स का गठन	(गृह विभाग)
3.	थानों में CCTV कैमरा/सोलर फोटोवोल्टइक सेल	(गृह विभाग)
4.	बाढ़ की तैयारी	(सिंचाई/कृषि/राजस्व विभाग)
5.	राहत की धनराशि का वितरण	(राजस्व विभाग)
6.	कृषक बीमा दुर्घटना एवं आम आदमी दुर्घटना बीमा योजना	(राजस्व विभाग)
7.	तहसीलों एवं ब्लाकों का उपलब्ध संसाधनों से कायाकल्प	(राजस्व विभाग)
8.	जन-सुनवाई	(सामान्य प्रशासन विभाग)
9.	क्लीन स्कूल, ग्रीन स्कूल	(माध्यमिक शिक्षा विभाग)
10.	कन्या विद्याधन की धनराशि रिलीज करना	(माध्यमिक शिक्षा विभाग)
11.	अमेठी, मैनपुरी एवं झाँसी में सैनिक स्कूल की स्थापना	(माध्यमिक शिक्षा विभाग)
12.	अभिनव विद्यालय	(माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग)
13.	समाजवादी पौष्टिक आहार योजना	(बेसिक शिक्षा विभाग)
14.	उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों को भरना	(बेसिक शिक्षा विभाग)
15.	लोहिया आवास योजना	(ग्राम्य विकास विभाग)
16.	वाटर ए.टी.एम. योजना	(ग्राम्य विकास विभाग)
17.	विधायकों को हैण्डपम्प की धनराशि	(ग्राम्य विकास विभाग)
18.	आई-स्पर्श योजना	(समन्वय, ग्राम्य विकास विभाग)
19.	नये विश्वविद्यालय के अधिनियम	(उच्च शिक्षा विभाग)
20.	राजकीय महाविद्यालय में लाइब्रेरी/कॉमन रूम में वाई-फाई सुविधा	(उच्च शिक्षा विभाग)
21.	नये राशन कार्डों का वितरण	(खाद्य-रसद विभाग)
22.	मजदूरों को भोजन	(श्रम विभाग)
23.	रोजगार मेला	(श्रम एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग)
24.	समाजवादी सर्वहित बीमा योजना	(संस्थागत वित्त विभाग)
25.	जवाहर बाग में पार्क	(उद्यान विभाग)
26.	सीतापुर में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क योजना	(वन विभाग)
27.	कामधेनु योजना	(पशुधन विभाग)
28.	अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना	(पशुधन विभाग)
29.	मल्टी परपज सचल पशु चिकित्सा सेवा	(पशुधन विभाग)
30.	पावरलूम विकास योजना	(हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग)
31.	हथकरघा बुनकरों की पेंशन योजना	(हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग)
32.	मण्डल मुख्यालयों पर डायलेसिस यूनिट की स्थापना	(चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

33.	काल सेन्टर आधारित शव वाहन सेवा योजना	(चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग)
34.	गॉव में सी.सी. रोड और ड्रेन निर्माण	(पंचायती राज विभाग)
35.	गॉव में अन्त्येष्टि स्थल का विकास	(पंचायती राज विभाग)
36.	हमीरपुर में जैविक खेती	(कृषि विभाग)
37.	बहराइच में किसान बाजार	(मण्डी परिषद)
38.	कन्नौज में आलू और मलीहाबाद में आम की मण्डी	(मण्डी परिषद)
39.	मण्डी परिषद के माध्यम से तिलहन प्रोसेसिंग यूनिट	(मण्डी परिषद)
40.	डा0 ए0पी0जी0 अब्दुल कलाम शहरी पुँज योजना	(नगर विकास विभाग)
41.	शहरो में अंत्येष्टि स्थल का विकास	(नगर विकास विभाग)
42.	स्टार्ट अप पालिसी	(आई0टी0 विभाग)
43.	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार गारण्टी योजना	(लघु उद्योग)
44.	वृद्ध महिला आश्रम	(महिला कल्याण विभाग)
45.	सभी जनपदों में आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना	(महिला कल्याण विभाग)
46.	हौसला योजना	(बाल विकास पुष्टाहार विभाग)
47.	माडल सिटी योजना	(आवास विभाग)
48.	रेडियो टैक्सी योजना	(परिवहन विभाग)
49.	अयोध्या-चित्रकूट धाम में भजन संध्या स्थल निर्माण	(धर्मार्थ कार्य विभाग)
50.	नये मिल्क प्लान्ट की स्थापना	(दुग्ध विकास विभाग)
51.	वृद्ध एवं अशक्तजनों के लिए गृह का निर्माण	(समाज कल्याण विभाग)
52.	विकास एजेण्डा की प्रगति	(समस्त संबंधित विभाग)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

क्र.सं.	महत्वपूर्ण प्राथमिकता का विवरण	विभाग का नाम	लक्ष्य (महत्वपूर्ण माइल स्टोन्स के साथ, जहाँ लागू हों)	संक्षेप में जून, 2016/ दिसम्बर, 2016 तक की गई कार्यवाही/प्रगति
1	2	3	4	5

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।